Seventeenth Loksabha

>

Title: Regarding grievances of people displaced due to Tehri Dam Project-laid.

श्रीमती माला राज्यलक्ष्मी शाह (टिहरी गढ़वाल): मैं केन्द्र सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र टिहरी गढ़वाल की ओर दिलाना चाहती हूं । टिहरी जिले में स्थित बहउददेश्यीय टिहरी बांध परियोजना से जुड़ी एजेसी सरकारी उपक्रम टीएचडीसी के अन्य सरकारी उपक्रम में विलय किये जाने की खबरों से टिहरी बांध विस्थापितों, प्रभावितों तथा पुनर्वासितों सहित उत्तराखंड के जनमानस के मध्य कई प्रकार की आशंकाएं उत्पन्न हो गई है ।

टिहरी बांध परियोजना, टिहरी व उत्तरकाशी जनपदों के हजारों परिवारों के राष्ट्रहित में त्याग का प्रतीक है । अभी तक भी टिहरी बांध के विस्थापित परिवारों की अनेक समस्याओं का समाधान होना शेष है । वहीं परियोजना में पूर्ववर्ती टिहरी स्टेट जो वर्तमान में राज्य का हिस्सा है, के हक हकूकों के बारे में भी निर्णय होना है । हरिद्वार और प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ व अर्द्धकुंभ के अवसर पर लगातार सुचारू जलापूर्ति किए जाने में टिहरी बांध रिजर्व जलाशय का योगदान रहता है । पूर्व में भारत सरकार द्वारा गठित हनुमंतराव समिति द्वारा स्वीकृत कई संस्तुतियों जिसमें बांध विस्थापित प्रभावितों को विभिन्न पुर्नवास स्थलों पर निशुल्क पेयजल उपलब्ध कराने तथा रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति करवाने के संबंध में अभी तक कोई योजना नहीं बनी है । जिससे बांध विस्थापित प्रभावित अपने को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं ।

मेरा सरकार से अनुरोध है कि परियोजना क्षेत्र के आसपास के गांवों को रियायती दर पर विद्युत आपूर्ति की जाए ।